बिहार विधान-सभा वादवृत्त।

भारत के संविधान के उपबन्ध के अनुसार एकत्र विधान-सभा का कार्य-विवरण।

सभा का अधिवेशन पटने के सभा सदन में सोमवार, तिथि २ दिसम्बर १९५७ को ११ बजे पूर्वाह्न में उपाध्यक्ष श्री प्रभुनाथ सिंह के सभापतित्व में हुआ।

अल्प-सूचित प्रश्नोत्तर।

Short-Notice Questions and Answers.

अपर यमुना स्कीम।

अ-१२६। श्री शुकदेव प्रसाद वर्मा—क्या मंत्री, सिंचाई विभाग, यह बताने की कृपा करेंगे कि—

(१) क्या यह बात सही है कि गया जिला के बेलागंज थाने में लक्ष्मीपुर ग्राम के पास अपर यमुना स्कीम के अन्दर यमुना नदी में पक्का बांध बांधा जा रहा है;

(२) क्या यह बात सही है कि अपर यमुना स्कीम से जो नहर निकाली गई है वह बेल्हाड़ी ग्राम की जमीन को दो हिस्सों में बांटती हुई आगे बढ़ी है;

(३) क्या यह बात सही है कि बेल्हाड़ी ग्राम की जमीन का पटवन पुराने आहर और पईन से होता है;

(४) क्या चार सौ बीघा जमीन जो नहर के उत्तर तथा पूरब पड़ गई है अब नहीं पट सकेगी और इसी वर्ष नहर की वजह से ही उस पार पानी नहीं जाने से धान की फसल मारी गयी;

(५) क्या सिंचाई विभाग ने शहर के उस पार की जमीन के पटवन के लिए पुराने आहर और पईन के पानी से नहर पार कर पटाने की कोई योजना बनायी है; यदि नहीं, तो इस जमीन के पटवन के लिए सरकार क्या प्रबंध करने को सोचती है?

*श्री केदार पान्डेय—(१) उत्तर स्वीकारात्मक है।

(२) उत्तर स्वीकारात्मक है।

(३) उत्तर स्वीकारात्मक है।

(४) चार सौ बीघे में करीब आधा रकवा नहर से पटेगा तथा बाकी के लिए सुपर पैसेज द्वारा पानी नहर को पार करेगा। इस वर्ष में आहर का पानी नहर में गिरा कर उस भूमि की सिंचाई लोगों ने की है। उपरोक्त उत्तर के अनुसार धान की फसल मारी गई यह बात सही नहीं है।

(५) नहर से नहीं पटने वाली जमीन का सिंचन करने के लिए एक छोटा सुपर पैसेज का प्रबंध किया गया है।

अ—प्रश्नकर्त्ता की अनुपस्थिति में श्री सत्येन्द्र नारायण अग्रवाल के अनुरोध पर उत्तर दिया गया।

अल्प-सूचित प्रश्न १४६ के सम्बन्ध में।

श्री केदार पान्डेय—उपाध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न का जवाब पहले दिया जा चुका है।

श्री रामानन्द तिवारी—उपाध्यक्ष महोदय, आपने जब इसे ऐडमिट कर लिया तो फिर इसके जवाब के सम्बन्ध में ये सब बातें कहां से उठती हैं?

उपाध्यक्ष—किसी स्टेज में गलती हो जाय और बाद में इसका पता चले तो इसे मान लेना चाहिए। उप-मंत्री जी का कहना है कि पहले भी ऐसा सवाल पूछा गया है और उसका जवाब भी हो चुका है इसलिए अब फिर इसे रिपीट करने से क्या लाभ है।

*श्री रामचरित्र सिंह—सिमिलर सवाल की बात तो दूसरी है। आज यह सवाल अगर पूछा जायगा तो इस पर बहुत-से पूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं जो उस दिन नहीं पूछे गये हों, इसलिए मेरा खयाल है कि इसे पेश करने की इजाजत देनी चाहिए।

श्री केदार पान्डेय—उपाध्यक्ष महोदय, इस सवाल पर उस दिन बहुत-से पूरक प्रश्न भी पूछे जा चुके ।

श्री राधानन्दन झा—हुजूर, यह सवाल पहले से स्थगित है।

उपाध्यक्ष—शान्ति, शान्ति, सिमिलर सवाल जब पूछा जा चुका है, जवाब भी दिया जा चुका है और पूरक प्रश्न भी पूछे जा चुके हैं, सब बातें खतम हो गयीं हैं, तो फिर से रिपीट करने को जरूरत नहीं मालूम पड़ती। लेकिन जब आपलोगों का कहना है तो मैं इसे स्थगित करता हूं। कार्यालय पहले प्रश्न से मिला कर देखेगा उसके बाद जैसा होगा किया जायेगा।

THERMAL POWER STATION AT BARAUNI.

182. **Shri RADHANANDAN JHA** : Will the Minister in-charge of the Electricity Department be pleased to state whether there is scheme before the State Government for the establishment of a thermal power station at Barauni consisting of two power plants of 15,000 K.W. each; if so, the progress so far made or is proposed to be made in this connection?

श्री केदार पान्डेय—उत्तर स्वीकारात्मक है। बरौनी पावर हाउस के लिए प्राप्त टेंडरों की जांच हो चुकी है। उनमें से तीनों प्रतियोगी फर्म प्रावैधिक दृष्टिकोण से योग्य पाये गये हैं। भुगतान के बारे में उन फर्मों के साथ पत्रालाप चल रहा है और उन सबों से अनुरोध किया गया है कि वे विदेशी मुद्रा विनिमय पर कठिनाई के फलस्वरूप भारतीय सरकार द्वारा उल्लिखित भुगतान अनुबन्ध करें। उनमें से कुछ प्रतियोगी फर्मों के उत्तर की प्रतिक्षा की जा रही है। उत्तर प्राप्त होने के उपरान्त इस योजना के सम्बन्ध में विदेशी मुद्रा विनिमय के निर्णय करने के हेतु पूर्ण स्थिति भारतीय सरकार के समक्ष रखी जायगी। शक्ति गृह एवं सम्बद्ध क्वार्टरों

के लिए भूमि ले ली गई है तथा क्वार्टरों के लिए रूपांकन एवं प्राक्कलन अंतिम रूप से तैयार कर लिया गया है।

श्री राधानन्दन झा—मैं सरकार से यह जानना चाहता हूं कि यह स्कीम सरकार के सामने कितने दिनों से है?

श्री केदार पान्डेय—यह मैं निश्चित नहीं बतला सकता लेकिन सेकेन्ड फाइव-ईयर प्लैन में है।

श्री राधानन्दन झा—उपाध्यक्ष महोदय, माननीय उप-मंत्री ने बतलाया है कि टेन्डर मांगा गया है और सब काम भी हो रहे हैं, लेकिन जिस समय यह स्कीम चलाई गई उस समय विदेशी विनिमय की बातें नहीं थीं इसलिए मैंने पूछा कि यह स्कीम कब से सरकार के सामने पेंडिंग है?

उपाध्यक्ष—उन्होंने तो बतलाया कि दूसरी पंचवर्षीय योजना में है, लेकिन ठीक समय अभी वे नहीं बतला सकते हैं।

श्री दीप नारायण सिंह—उपाध्यक्ष महोदय, इस सम्बन्ध में एक बात मैं साफ कह देना चाहता हूं कि शायद कुछ लोगों के मन में यह शंका है कि यह स्कीम छोड़ दी गई है लेकिन ऐसी बात नहीं है। इसे चालू करने की पूरी तैयारी और कोशिश की जा रही है। जमीन भी खरीदी जा रही है। इसलिए इसमें किसी तरह का शक या शंका नहीं होनी चाहिए।

श्री राधानन्दन झा—मैं यह पूछना चाहता हूं कि केन्द्रीय सरकार को इस सम्बन्ध में पहले-पहल कब लिखा गया?

श्री केदार पान्डेय—केन्द्रीय सरकार के यहां से जो पत्र आया है वह २० अगस्त १९५७ को मिला है। केन्द्रीय सरकार उसमें लिखा है कि फर्मों ने जो औफर दिए हैं उनसे वह राजी नहीं है। केन्द्रीय सरकार का कहना है कि मेटीरियल की डेलिवरी वगैरह के सम्बन्ध में २० प्रतिशत पेमेन्ट किया जायगा और इसके बाद ८० प्रतिशत जो लागत है उसका ७ इक्वल इन्सटालमेन्ट्स में डेफर्ड पेमेन्ट होगा। ये जो तीन-फर्म्स हैं उनमें इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट लि० का औफर सबसे ज्यादा फेवरेबुल है। बात-चीत हो रही है और माइनर डिफरेन्सेज डेफर्ड पेमेन्ट के सम्बन्ध में जो हैं, उसके बारे में उम्मीद की जाती है कि ठीक हो जायगा और फर्म उसके लिये तैयार हो जायगा। फर्म का कहना है कि ५ इक्वल इन्सटालमेन्ट्स में पेमेन्ट हो, कुछ अभी हो और बाकी बाद में पेमेन्ट किया जाय। और केन्द्रीय सरकार कहती है कि ७ इसटालमेन्ट्स में पेमेन्ट करेंगे। बातचीत हो रही है और फर्म ने अपने हेडऑफिस को लिखा है। इस स्टेज में यह बात पहुंची है। इसमें कोई शक नहीं है कि बरौनी थर्मल स्टेशन स्टैब्लिश जरूर किया जायगा। काम आगे बढ़ा दिया गया है और कार्रवाई जो बाकी है की जायगी।

श्री देव नारायण यादव—मैं सरकार से यह जानना चाहता हूं कि दूसरी पंच-वर्षीय योजना में सरकार इस योजना का कब सम्पादन करने जा रही है?

श्री केदार पान्डेय—हमने तो कहा कि दूसरी पंचवर्षीय योजना में यह है लेकिन कितना समय इसमें लगेगा यह कहना कठिन है।

श्री देव नारायण यादव—सरकार ने अभी बतलाया कि टेंडर वगैरह मांग लिया गया है और कार्रवाई हो रही है इसलिए हमने पूछा कि इसे आप कब शुरू करने जा रहे हैं?

श्री केदार पान्डेय—उपाध्यक्ष महोदय, हमने बतलाया है कि भारतीय सरकार और फर्मों के बीच कुछ माइनर डिफरेन्सेज हैं। जैसे ही वे दूर हो जायेंगे हमलोग काम शुरू कर देंगे।

श्री देव नारायण यादव—मैं जानना चाहता हूं कि फौरेन एक्सचेन्ज की वजह से जो दिक्कत होती है वही फौरेन एक्सचेन्ज वाला मामला इस स्कीम के मुत्तलिक तो नहीं उठेगी?

श्री केदार पान्डेय—मैंने कहा कि डेफर्ड पेमेन्ट की बात है इसलिये यह सवाल नहीं उठता है।

श्री देव नारायण यादव—मैं जानना चाहता हूं कि जब फौरेन एक्सचेन्ज की दिक्कत नहीं होगी तो क्या सरकार इस योजना को शीघ्र लागू करेगी?

उपाध्यक्ष—सरकार ने कह दिया है कि डेफर्ड पेमेन्ट का इन्तजाम ७ इन्सटालमेंट्स में किया गया है।

श्री देव नारायण यादव—मैं जानना चाहता हूं कि इस दिक्कत के बावजूद भी क्या सरकार अपने स्ट्रेन्थ पर इस योजना को लागू कर सकती है या नहीं?

उपाध्यक्ष—माननीय मंत्री ने कहा है टु दी बेस्ट ऑफ आवर एबीलिटी वि शैल पुश इट। इसके बाद सवाल कहां उठता है?

*श्री चन्द्रशेखर सिंह—मैं जानना चाहता हूं इस स्कीम का टोटल फौरेन एक्सचेंज रिक्वायरमेंट क्या है?

श्री केदार पान्डेय—इसमें करीब दो करोड़ चालीस लाख रुपए लगेंगे।

श्री चन्द्रशेखर सिंह—क्या फौरेन एक्सचेंज रिक्वायरमेंट के बारे में सेन्ट्रल गवर्नमेंट को लिखा गया है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में सेन्ट्रल गवर्नमेंट से कितना फौरेन एक्सचेंज अभेलेबुल करने के पोजीशन में है?

श्री केदार पांडेय—बात यह है कि २० प्रतिशत केन्द्रीय सरकार देने के लिये तैयार है। बाकी के लिए १९६० के बाद ही पेमेन्ट का सवाल उठेगा।

श्री फजलुर रहमान—मैं जानना चाहता हूं कि किन-किन फर्मों ने टेन्डर दिया था?

श्री केदार पान्डेय—तीन इम्पौर्टेन्ट फर्म्स हैं जिनके विषय में केन्द्रीय सरकार ने स्टेट गवर्नमेंट से पूछा है। उन फर्मों के नाम ये हैं:

(१) मेसर्स इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट लिमिटेड।

(२) मेसर्स जी० सी०।

(३) कुल्जन कारपोरेशन।

श्री फजलुर रहमान—मैं जानना चाहता हूं कि किसी फर्म ने ऐसा भी कन्डीशन रखा है कि अगर हमारा टेन्डर ऐक्सेप्ट किया जाय तो फौरेन एक्सचेंज का सवाल हमारे साथ नहीं उठेगा?

श्री केदार पांडेय—इसकी जानकारी हमें नहीं है।

सुलतानगंज शहर का विद्युत्करण।

अ-१८७। श्रीमती सरस्वती देवी—क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि—

(१) क्या यह बात सही है कि भागलपुर जिला के सुलतानगंज थाने में पटवन का इन्तजाम नहीं है;

(२) क्या यह बात सही है कि निकट भविष्य में सुलतानगंज शहर का विद्युत्करण होने वाला है;

(३) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त सुलतानगंज थाने में लिफ्ट इरीगेशन के द्वारा सिंचाई की व्यवस्था पर विचार करेगी, यदि नहीं, तो क्यों?

श्री केदार पांडेय—(१) उत्तर स्वीकारात्मक है।

(२) उत्तर स्वीकारात्मक है किन्तु जून, १९५९ तक इस क्षेत्र को मिलनेवाली बिजली शक्ति की मात्रा बहुत थोड़ी होगी।

अ—प्रश्नकर्त्ता की अनुपस्थिति में श्री यदुनन्दन झा के अनुरोध पर उत्तर दिया गया।